चंबल पर 2.3 किमी एक्वाडक्ट का निर्माण जून 2028 तक पूरा होगा- भजनलाल

राम जलसेतु लिंक के प्रथम चरण में बन रहे एक्वाडक्ट पर 2,330 करोड़ रूपए खर्च होंगे

जयपुर, 18 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत् प्रयासों से प्रदेश की महत्वाकांक्षी राम जलसेतु लिंक परियोजना (संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना) मिशन मोड पर आगे बढ़ रही है। जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली परियोजना के तहत चम्बल नदी पर 2.3 किलोमीटर लम्बाई में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह जून, 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

मुख्यमंत्री शर्मा के मार्गदर्शन में परियोजना से संबंधित कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। इसके प्रथम चरण के पैकेज-2 के अंतर्गत, 2 हजार 330 करोड़ रुपये की लागत से एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है।

यह चम्बल एक्वाडक्ट एक छोर में कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले की इन्द्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव से जुड़ेगा। इसके माध्यम से कालीसिंध पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी पम्प हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मैज बैराज से पम्प हाउस व फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बीसलपुर और ईसरदा बांध में पहुंचाया जाएगा। इस एक्वाडक्ट के बनने से आमजन को

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- इस परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही सिंचाई व उद्योग के लिए भी जल उपलब्ध होगा।

आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा।

2280 मीटर लम्बे एक्वाडक्ट की आंतरिक चौड़ाई 41.25 मीटर और ऊंचाई 7.7 मीटर प्रस्तावित है। मई, 2025 में कार्य शुभारंभ के बाद से ही तेजी से कार्य किया जा रहा है।

निर्माण स्थल पर कैंप एवं बैचिंग प्लांट का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एक्वाडक्ट हेतु प्रस्तावित 15 टेस्ट पाइल में से 8 टेस्ट पाइल का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 5060 वर्किंग पाइल प्रस्तावित हैं, जिनमें से लगभग 860 पाइल का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। प्रतिदिन 15-20 पाइल का कार्य 12 रिग मशीनों की सहायता से किया जा रहा है। औसतन 500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है। साइट पर लगातार शिफ्टों में कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ईआरसीपी को वृहद स्वरूप देते हुए राम जलसेतु लिंक परियोजना (संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना) (लगभग 90 हजार करोड़ रूपए) तैयार की गई है। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही, सिंचाई एवं उद्योगों के लिए भी जल उपलब्ध होगा। इससे प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

केवाईसी के नाम पर क्रेडिट कार्ड का क्लोन बना लाखों की ठगी

जयपुर, 18 जनवरी। महेश नगर थाना इलाके में क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनाकर केवाईसी के नाम से लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि थाना इलाके में स्थित अवधपुरी निवासी सुमन लाल महावर (41) ने मामला दर्ज कराया है कि उसके पास एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड की केवाईसी करवाने के नाम पर उनके पास लगातार कॉल आ रहे थे। कॉल करने वाले ने खुद को एसबीआई बैंक का प्रतिनिधी बताया और केवाईसी के लिए उसके मोबाइल पर लिंक भी भेजा। अज्ञात ठग ने बातों में उलझा कर क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी जुटा ली और क्रेडिट कार्ड का क्लोन तैयार कर, दो लाख 60 हजार रुपए निकाल लिए। पीड़ित को मामले की जानकारी उसके मोबाइल फोन पर आए मैसेज से चली, जिसके बाद पीड़ित ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ धोखाधड़ी कर उसके कार्ड से पैसे निकालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया।

सोलह लोगों को कुचलने वाला ऑडी चालक गिरफ्तार

पुलिस ने रविवार को रिंग रोड पर चलाये गये सर्च ऑपरेशन में उसे पकड़ा

जयपुर, 18 जनवरी। पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 जनवरी को मानसरोवर के खरबास सर्किल पर ऑडी कार से 16 लोगों को रौंदने वाले मुख्य आरोपी चालक दिनेश रणवा (32) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने रविवार को रिंग रोड पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान उसे दबोच लिया।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि आरोपी दिनेश रणवा निवासी दूधवाखारा जिला चूरू हादसे के बाद से फरार था। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के अगले दिन वह गोनेर से पैदल ही भाग निकला। कैमरों से बचने के लिए रिंग रोड के किनारे-किनारे पैदल चलता रहा। करीब 7-8 घंटे पैदल चलने के बाद जंगल में झाड़ियों के बीच थक कर

- आरोपी ऑडी चालक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर करनाल व हरिद्वार चला गया था। पैसे खत्म होने के बाद वापस लौटा था और रिंग रोड क्षेत्र में घूम रहा था।

रुक गया।

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि चोटिल होने और लगातार भागने से वह बेहद थक गया था। आस पास भेड़ चराने वालों से मांग कर खाना खाया और रात उनके पास ही सो गया। इसके बाद एक ट्रक चालक से लिफ्ट लेकर पहले करनाल (हरियाणा) और फिर हरिद्वार पहुंचा। पैसे खत्म होने पर वह वापस राजस्थान लौटा और जयपुर के पास रिंग रोड क्षेत्र में घूमता रहा। पुलिस जांच में सामने आया कि दिनेश हाईवे किनारे होटल-ढाबों और ट्रक रुकने की जगहों पर फरारी काट रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 100 किलोमीटर क्षेत्र में लगे 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। रिंग रोड, स्लिप रोड, ढाबों और ट्रक स्टॉप्स पर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आरोपी के सोलर प्लांट साइट्स पर भी दबिश दी गई। आखिरकार रविवार को रिंग रोड पर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गौरतलब है कि 9 जनवरी को दिनेश रणवा ने तेज रफ्तार ऑडी कार को मानसरोवर के खरबास सर्किल पर सड़क किनारे लगे स्टॉलों में घुसा दिया था। हादसे में 16 लोग चपेट में आ गए, जिनमें एक युवक की मौत हो गई थी।

डिफेन्स सैक्टर को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं- राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक डिफेन्स एक्सपोर्ट 50 हजार करोड़ रूपए का हो जाए

नागपुर, 18 जनवरी। केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। न जाने कब हमें हथियारों की जरूरत पड़ जाए। इसलिए डिफेंस सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने नागपुर में यह बात कही। वे आज इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव कंपनी के दौरे पर पहुंचे थे।

इस दौरान रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डिफेंस सेक्टर को हम लोग आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बार-बार इसका आग्रह कर रहे हैं। एक समय था कि पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर तक सीमित था, प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की पोटेंशियल पर हमको पूरा भरोसा था, विश्वास था, हर जगह फोक्स्ड डेवलपमेंट की धारा बह रही है, शिक्षक से लेकर तकनीक तक, हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर अहम भूमिका निभा रहा है।

- रक्षा मंत्री ने नागपुर में कहा, हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब हरकत कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता, न जाने कब हमें हथियारों की जरूरत पड़ जाए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका आने वाले समय में और तेजी से बढ़ ने चाहिए और भारत में बढ़ रही है। हमारी सरकार का ध्यान आने वाले समय में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पर है। यह कम से कम 50 प्रतिशत तो होनी भी चाहिए। हमने निश्चय किया है कि हमारे प्लेटफार्म सिस्टम, सब सिस्टम धीरे-धीरे स्वदेशी बनाएंगे, पिछले 10 वर्ष में डिफेंस सेक्टर में, आत्मनिर्भरता की दिशा में, जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, उसका परिणाम यह है कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 2014 में 46000 करोड़ के आसपास था, आज वह डेढ़ लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। इतनी जल्दी, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का परिणाम है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, जो 10 वर्ष पहले सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास था, वह बढ़ कर लगभग 25000 करोड़ से ज्यादा हो गया है, हमने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक यह 50000 करोड़ तक हो जाए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत हथियारों के उत्पादन का ग्लोबल हब बने। उन्होंने कहा 88 घंटे तक ऑपरेशन चला, लेकिन वो 88 घंटे शब्दों में बयां नहीं किये जा सकते, इसको शब्दों में बताना मुश्किल है, ऐसे ऑपरेशन में हर मिनट हर फैसले का महत्व होता है, जब ऑपरेशन इतना इंटेंस होता है, तो उसकी तैयारी भी इतनी व्यापक उतनी मजबूत होनी चाहिए।

मकान मालिक के 52 लाख चुराने वाला नौकर गिरफ्तार

जयपुर, 18 जनवरी। बजाज नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के घर से घरेलू नौकर द्वारा 52.50 लाख रुपए नकद चोरी करने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी नौकर को बिहार से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की राशि बरामद कर ली है। भारी रकम होने के कारण नकदी को जयपुर लाने के लिए हथियारबंद जवानों की विशेष टीम भेजी गई।

एसीपी विनोद शर्मा ने बताया कि देवनगर निवासी निखिल अग्रवाल ने 12 जनवरी को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वे परिवार सहित 1 जनवरी को बाहर गए थे, इसी दौरान

- पुलिस ने आरोपी नौकर को बिहार से गिरफ्तार किया तथा चोरी की रकम बरामद की।

उनके घर से नकदी चोरी हो गई। उन्होंने अपने घरेलू नौकर पर संदेह जताया था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें एक व्यक्ति दीवार फांदकर घर में घुसता नजर आया। परिवादी ने फुटेज के आधार पर उसकी पहचान घरेलू नौकर मंटू उर्फ रामू उर्फ मनोज ठाकुर के रूप में की। तकनीकी विश्लेषण से आरोपी की लोकेशन बिहार में मिलने पर पुलिस टीम को बांका जिले के देवंडीह गांव भेजा गया, जहां बिहार पुलिस की मदद से चालीस वर्षीय मन्टू उर्फ रामू उर्फ मनोज ठाकुर निवासी बेलहर जिला बांका (बिहार) को हिरासत में लिया गया।

एसीपी शर्मा ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट में करीब 22 लाख रुपए चोरी होने की जानकारी दी थी, लेकिन पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने मकान मालिक के विदेश जाने के दौरान ताले तोड़कर 52.50 लाख रुपए चुराए थे। आरोपी को बांका जिले की अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। रकम अधिक होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से एक अलग हथियारबंद टीम को बिहार भेजा गया, जो आरोपी और नकदी को सुरक्षित जयपुर लेकर आई।

दिल्ली में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा

सफदरगंज में कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही तथा पालम में 100 मीटर दर्ज हुई

नयी दिल्ली, 18 जनवरी। राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग में रविवार सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य हो गई, जबकि पालम में यह 100 मीटर दर्ज की गयी।

मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी है और कई केन्द्रों में न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस, पालम में न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस और आया नगर में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

विभाग ने कहा कि दिल्ली के कई हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है और ऐसी स्थिति सुबह और रात के घंटों के दौरान जारी रहने के

- मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार-पाँच दिन उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी।

आसार हैं। मौसम विभाग ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने के आसार हैं। इसके बाद अगले छह दिनों में तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने का अनुमान है। वहीं 21 और 22 जनवरी को सामान्य से नीचे और 19, 20 और 23 जनवरी को सामान्य से ऊपर रहेगा। अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं, जिसके बाद यह सामान्य हो जाएगा। विभाग ने बताया है कि अगले सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में शीतलहर की संभावना नहीं है। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ 18 जनवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करता रहेगा, जबकि 19 और 21 जनवरी, 2026 को उत्तर-पश्चिम भारत में दो और विक्षोभ आने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी।

'प्रतीकात्मक रूप से भी नोबेल पुरस्कार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता'

वाशिंगटन, 18 जनवरी। साल 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वेनेज़ुएला की नेता मारिया मचादो द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना प्राइज ट्रांसफर करने पर नोबेल कमेटी का बड़ा बयान सामने आया है। नोबेल फाउंडेशन ने कहा कि हमारा एक मुख्य उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों की गरिमा और उनकी प्रशासनिक प्रक्रिया की रक्षा करना है। फाउंडेशन अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत और उसके प्रावधानों का सख्ती से पालन करता है। वसीयत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाएंगे, जिन्होंने "मानवजाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया हो"। कमेटी ने कहा कि यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक पुरस्कार किस संस्था या समिति को प्रदान करने का अधिकार है।

राज्य के 20 दिग्गज नेता भाजपा अध्यक्ष के प्रस्तावक बनेंगे

जयपुर, 18 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी के घोषित कार्यक्रम के अनुसार 19 जनवरी को नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि 20 जनवरी को परिणाम घोषित होंगे। मौजूदा समय में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन इस पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना जताई जा रही है।

नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहने की संभावना है। इस पूरे चुनावी घटनाक्रम

- प्रस्तावकों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा, मदन राठौड़, वसुंधरा राजे, भूपेन्द्र यादव, गजेन्द्र शेखावत, अर्जुन मेघवाल, भागीरथ चौधरी, राजेन्द्र राठौड़, सतीश पूनिया, अल्का गुर्जर, अरूण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, सीपी जोशी, घनश्याम तिवाड़ी व मंजू शर्मा शामिल हैं।

में राजस्थान की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए राजस्थान से पार्टी के करीब 20 वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है। इन नेताओं के हस्ताक्षर युक्त प्रस्तावों की सूची 18 जनवरी को दिल्ली भेजी जाएगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ स्वयं यह सूची लेकर दिल्ली जाएंगे और इसे चुनाव अधिकारी को सौंपेंगे।

प्रस्तावकों की सूची में राज्य सरकार, संगठन और केन्द्र सरकार से जुड़े बड़े नाम शामिल किए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी प्रमुख हैं।

इसके अलावा, संगठन और वरिष्ठ नेतृत्व का संतुलन साधते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, हरियाणा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अल्का गुर्जर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी और सीपी जोशी को भी प्रस्तावक बनाया गया है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, मंजू शर्मा सहित, कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम भी सूची में शामिल हैं। फिलहाल जयपुर और दिल्ली में मौजूद नेताओं के हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। सभी हस्ताक्षर पूरे होते ही प्रस्तावकों की अंतिम सूची दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी जाएगी।

कोई नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"एकनाथ शिंदे ने ताज होटल को जेल बना दिया है। वहां लगभग 25 से 29 पार्षदों को इस डर से बंधक बनाकर रखा गया है कि कोई उन्हें किडनैप कर लेगा या धमकाएगा।"

उन्होंने मांग की कि उन लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। संजय राउत ने भाजपा और शिंदे गुट के गठबंधन में दरार होने का संकेत देते हुए बड़ा दावा किया। राउत ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि मुंबई में भाजपा का मेयर बने, यहां तक कि खुद एकनाथ शिंदे भी ऐसा नहीं चाहते।

उन्होंने यह कहकर खलबली मचा दी कि शिंदे गुट के कई पार्षद यूबीटी शिवसेना के संपर्क में हैं। राउत ने साफ कहा, "हमारे संपर्क में कई लोग हैं।"

यूरोपीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को हासिल करने पर आमादा हैं। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अपने आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर देते हुए इस विचार को खारिज कर दिया है।

बढ़ ते तनाव के जवाब में, डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है, जबकि जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे और नीदरलैंड ने भी छोटी सैन्य टुकड़ियाँ भेजी हैं। यूरोपीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के किसी भी अमेरिकी प्रयास का नाटो और अटलांटिक के दोनों ओर की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

पूर्णतया डॉलर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खुद को खतरे में पा सकती हैं।

भारत, जो अपने कच्चे तेल का चार-पांचवां (4/5) हिस्सा आयात करता है, रूस के साथ लंबे समय से डिफेंस संबंध बनाए रखता है और वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया के साथ बढ़ता हुआ ट्रेड करता है, उसके लिए बिना रुकावट वाले पेमेंट चैनल पक्का करना एक स्ट्रेटेजिक चिंता बन गया है। ब्रिक्स ब्रिज को, इंटरनेशनल बैन का उल्लंघन किए बिना, या डिप्लोमैटिक टकराव को भड़काए बिना इस कमज़ोरी को कम करने के एक तरीके के तौर पर देखा जा रहा है।

इस प्लेटफॉर्म को खुद एक डिजिटल, मल्टीलेटरल सेटलमेंट मैकेनिज़्म के तौर पर देखा गया है, जो हिस्सा लेने वाले देशों को अपनी लोकल करेंसी में क्रॉस-बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन करने की इजाज़त देता है, जिसमें बाद के स्टेज में सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को इंटीग्रेट करने की क्षमता है। स्विफ्ट के विपरीत, जो मुख्य रूप से फाइनेंशियल मैसेजिंग की सुविधा देता है और अभी भी वेस्टर्न बैंकों के ज़रिए डॉलर क्लियरिंग की ज़रूरत होती है, ब्रिज का मकसद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच डायरेक्ट सेटलमेंट को मुमकिन बनाना है। थ्योरी के हिसाब से, इससे इंडियन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर न्यूयॉर्क या लंदन के ज़रिए भुगतान भेजे बिना लेनदेन कर सकेंगे।

यह तरीका भारत की हालिया पॉलिसी ट्रैजेक्टरी से काफी मिलता-जुलता है। पिछले कुछ सालों में, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड में रुपये के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सावधानी भरे कदम उठाए हैं, जैसे रुपए में सैटलमैंट की व्यवस्था, द्विपक्षीय व्यापार के लिए विशेष वोस्ट्रो खाते और डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजैक्ट। इसलिए ब्रिक्स ब्रिज भारत की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि करेंसी डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में इसके धीरे-धीरे और सोच-समझकर किए गए प्रयासों का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है।

ब्रिक्स फाइनेंशियल इनिशिएटिव में भारत की भागीदारी हमेशा से संयम से पहचानी गई है। चीन या रूस के विपरीत, नई दिल्ली दुनिया की रिज़र्व करेंसी के तौर पर डॉलर को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है और न ही वह डी-डॉलराइज़ेशन को पश्चिम के साथ जियोपॉलिटिकल मुकाबले के तौर पर देखना चाहता है। इसके बजाय, भारत का मकसद रिस्क मैनेजमेंट है। दूसरे पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट करके, वह यह पक्का करना चाहता है कि ऊर्जा, उर्वरक, रक्षा उपकरण और अन्य जरुरी वस्तुओं का व्यापार भू-राजनीतिक तनाव के समय भी जारी रह सके। रुस से रियायती तेल की बढ़ी हुई खरीद के दौरान यह साफ दिखा, जब बैन से जुड़ी रुकावटों के बावजूद ट्रेड को चालू रखने के लिए नए सेटलमेंट मैकेनिज़्म बनाने पड़े। ट्रेड से जुड़े साफ़ फायदे भी हैं। ब्रिक्स मेंबर्स और बड़े ग्लोबल साउथ के साथ भारत का इकोनॉमिक जुड़ाव लगातार बढ़ा है, और इनमें से कई अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर की लगातार कमी या ग्लोबल लिक्विडिटी तक, अस्थिर एक्सेस का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मुद्रा में सेटलमेंट का प्लेटफॉर्म ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट कम कर सकता है, डॉलर के उतार-चढ़ाव का रिस्क कम कर सकता है और भारतीय बिज़नेस, खासकर छोटे और मीडियम एक्सपोर्टर्स, जो नए मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, के लिए सेटलमेंट साइकिल को छोटा कर सकता है।

साथ ही, भारत ब्रिक्स के अंदर के समीकरणों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है। चीन डी-डॉलराइज़ेशन का सबसे मुखर समर्थक बनकर उभरा है और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों को, युआन को इंटरनेशनलाइज़ करने के एक टूल के तौर पर देखता है। हालांकि, भारत ऐसे किसी भी फ्रेमवर्क से सावधान है, जो युआन-डोमिनेटेड इकोसिस्टम में बदल सकता है। यही वजह है कि नई दिल्ली ब्रिक्स ब्रिज के लिए बहुमुद्रा और नियम आधारित ढांचे पर जोर देती है और तेज विस्तार के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ना पसंद करती है। भारतीय पॉलिसी बनाने वाले भी इस प्लेटफॉर्म की सीमाओं को समझते हैं। ब्रिक्स ब्रिज स्विफ्ट का विकल्प बनने से बहुत दूर है। कई सदस्य देशों में गहरे और लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट की कमी, असमान रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, करेंसी में उतार-चढ़ाव और साइबर सिक्योरिटी और डेटा गवर्नेंस से जुड़े अनसुलझे सवाल, ये सभी इसकी तुरंत उपयोगिता को सीमित करते हैं। भारत का अपना कैपिटल अकाउंट भी पूरी तरह से कन्वर्टिबल नहीं है, जिससे यह सीमित हो जाता है कि रुपये को कितनी आक्रामकता से ग्लोबल मंच पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

फिर भी भारत के लिए, यह पहल एक और महत्वपूर्ण मकसद पूरा करती है। यह रुपये की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका का टेस्ट करने के लिए एक कंट्रोल्ड माहौल प्रदान करती है, जिसके लिए रिजर्व-करेंसी का दर्जा पाने की इच्छा रखने के बजाय, खुले कैपिटल मार्केट और लगातार करंट-अकाउंट सरप्लस की आवश्यकता होती है। भारत व्यापार और सेटलमेंट में रुपये के फंक्शनल उपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस दिशा में मामूली फायदे भी विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करते हैं और मैक्रोइकोनॉमिक लचीलेपन को मजबूत करते हैं।

आखिरकार, ब्रिक्स ब्रिज को डॉलर के लिए एक बड़े चैलेंज के रूप में कम और लंबे समय के इरादे के संकेत के रूप में अधिक देखा जाना चाहिए। भारत की रणनीति क्रांतिकारी नहीं, बल्कि विकासात्मक है। यह मौजूदा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में मजबूती से बने रहते हुए चुपचाप विकल्प बनाने के बारे में है।

डॉलर शायद, दशकों तक नहीं, तो सालों तक अपना दबदबा बनाए रखेगा। लेकिन भारत, कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तरह, अब नहीं चाहता कि उसका सारा फाइनेंशियल फ्लो एक ही गेटकीपर से होकर गुजरे। ब्रिक्स ब्रिज, भले ही अभी सीमित और शुरुआती चरण में हो, लेकिन यह फायनैंस में रणनीतिक स्वायत्तता की भारत की व्यापक कोशिश को दर्शाता है, जैसा उसका रवैया कूटनीति और रक्षा में भी रहा है, जहां लचीलापन, संतुलन और विकल्प, विचारधारा या टकराव से ज्यादा मायने रखते हैं।

त्रिवेणी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

श्रद्धालुओं का साथ दिया और खिली-खिली धूप में लोग स्नान करते रहें। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि आज शाम पांच बजे तक चार करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान करने वाले लोगों पर हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई।

मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है। मेला प्राधिकरण का अनुमान था कि आज के दिन तीन से साढ़े तीन करोड़ लोग स्नान करेंगे लेकिन दो बजे तक ही तीन करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया था।

लिहाज़ा ये आकड़ा और बढ़े गा, श्रद्धालुओं की भीड़ क़ो देखते हुए पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार कल देर रात 12 बजे से ही घाट पर डटे रहे और खुद ही पूरी व्यवस्था की निगरानी करते रहे।

ट्रंप ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रस्ताव पर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यदि भारत इस पहल में शामिल होता है, तो यह पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया में उसकी भूमिका को और मजबूत कर सकता है।

संयुक्त अरब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रदान से मिली मज़बूत गति पर आधारित है, जिसमें सितंबर 2024 में अबू धाबी के शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की यात्रा और पिछले वर्ष अप्रैल में अमीरात के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तथा दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की यात्रा शामिल हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध हैं, जो मज़बूत राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित हैं। दोनों देश एक-दूसरे के शीर्ष व्यापार और निवेश साझेदारों में से हैं, जिन्हें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते , स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और द्विपक्षीय निवेश संधि से बढ ावा मिला है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मज़बूत ऊर्जा साझेदारी भी है, जिसमें दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था शामिल है।

तृणमूल सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में बनने वाले एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम (समुद्री बंदरगाह के गेट को बंदरगाह से बढ़ाना) का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे हुगली और आसपास के क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे।

कोलकाता शहर पर ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा और गंगा जलमार्ग के जरिए कार्गो मूवमेन्ट में तेजी आएगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार बहुस्तरीय संपर्क और हरित चालन (ग्रीन मोबिलिटी) पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि बंदरगाह, नदी जलमार्ग, राजमार्ग और हवाई अड्डे एक-दूसरे से जुड़ें और किराया लागत तथा समय दोनों में कमी आए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल सरकार केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर लागू नहीं होने देती। उन्होंने राजधानी दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी एक सरकार आयुष्मान भारत योजना को रोक रही थी, लेकिन जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया और अब दिल्ली में गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि बंगाल में भी भाजपा की सरकार जरूरी है, ताकि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचे।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्